

आज का विचार

महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं

# पंजाब रिफ्लैक्शन

## पंजाब रिफ्लैक्शन

पंजाब रिफ्लैक्शन  
निडुल्लेपेठ ठुं पंजाब 'ਚ  
ਪੱਤਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ  
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ-  
88375-75230  
94174-91941

वर्ष-1, अंक-50, रजिस्ट्रेशन नं. : PUNBIL01282, जालंधर, संपादक-नीतू कपूर, दोभाषायी (हिन्दी पंजाबी), पक्षिक, कीमत-5 रूपए, 21 मार्च 2021, मोबाईल 94174-91941, 88375-75230, Email : punjabreflection@gmail.com

## मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान आकर्षण रहेगी खादी की मुजीब जैकेट्स

रिफ्लैक्शन ब्यूरो  
खादी मुजीब जैकेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले सप्ताह का दो दिवसीय यात्रा के दौरान आकर्षण का केंद्र होगा। भारतीय उच्चायोग में अधिकारी बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में उनके सिगनेचर परिधान को पहनेंगे। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को 100 ऐसे कस्टम-डिजाइन किए गए %मुजीब जैकेट्स% की आपूर्ति की है। केवीआईसी के अध्यक्ष, विनाई कुमार सक्सेना ने कहा, 26-27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र की राजनयिक यात्रा के दौरान परिधान गणमान्य लोगों की प्रमुख पोशाक होगी। पुरानी पीढ़ी के लिए, यह उनके महान नेता की विचारधारा का प्रतीक है, जबकि यह बांग्लादेश के युवाओं के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। मोदी हमेशा देशों के साथ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए खादी और इसकी विरासत और सांस्कृतिक मूल्य के पक्षधर रहे हैं। 2016 में, ब्रिक्स नेताओं, जिसमें मोदी भी शामिल हैं, ने गोवा में खादी जैकेट में शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। सक्सेना ने कहा, प्रधानमंत्री



ने अपनी राजनयिक यात्राओं के दौरान हमेशा खादी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यह महात्मा गांधी की विरासत को आगे ले जाने के लिए है, जो हमेशा खादी उत्पादों को विशेष रूप से खादी के रूमाल विदेशी दौरों के दौरान वहां के पदाधिकारी को सम्मान स्वरूप देते थे। विशेष रूप से डिजाइन किया गया मुजीब जैकेट उच्च गुणवत्ता वाले दस्तकारी खादी कपड़े से बना है। ब्लैक मुजीब जैकेट को छह बटन, निचले आधे हिस्से पर दो जेब और बाईं ओर एक फ्लॉट पॉकेट के साथ डिजाइन किया गया है। कपड़े के पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति के ध्यान में रखते हुए, इन जैकेटों के लिए जिप-कवर भी खादी इंडिया लोगों के साथ काले सूती कपड़े से बने हैं। मुजीब जैकेट बांग्लादेश में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है और यह बहुत गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान खादी के कपड़े से बने इन जैकेटों को सुशोभित किया जाएगा, जो खादी के सबसे बड़े ब्रांड एंबेसडर हैं। उन्होंने कहा, खादी से बने मुजीब जैकेट इस समारोह के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगे। यह खादी को वैश्विक और राजनयिक मंच पर भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा।

## कृषि कानून को लेकर 110 दिन से प्रदर्शन जारी

आंदोलनकारी किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे होली



रिफ्लैक्शन ब्यूरो  
कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 110 दिन से अधिक समय से किसानों का प्रदर्शन जारी है, देशभर में आगामी दिनों में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, ऐसे में किसानों ने भी ये तय कर लिया है कि वे होली दिल्ली की दहलीज पर ही मनाएंगे। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि 28 मार्च को होली दहन के दिन किसान विरोधी कानूनों को जलाया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने होली दहन की तैयारी पूरी

कर ली है, आंदोलन स्थल पर तकरीबन आधा दर्जन वसंत रखे गए हैं, आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही राकेश टिकैत साफ कर चुके थे कि किसान होली भी इस बार गाजीपुर बॉर्डर पर ही मनाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के उत्तरप्रदेश अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने बताया, इस बार सभी किसान यहीं होली मनाएंगे। आंदोलन अभी जारी है, ऐसे में किसान गांव नहीं जाएंगे। बॉर्डर पर ही इस बार सादगी और शांतिपूर्ण तरह से होली मनाई जाएगी। सरकार के खिलाफ नाराजगी

जताते हुए, क्या होली के दिन किसी तरह कोई हुड़दंग किया जाएगा? इस सवाल के जवाब में जादौन ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, न कोई उग्र होगा न हुड़दंग होगा। पूरे शांतिपूर्ण तरह से इसे किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेश मलिक ने बताया, होली एक बड़ा त्यौहार है, किसान घर न जाकर गाजीपुर बॉर्डर पर ही होली मनाएंगे। सत्य को अग्नि भी पराजित नहीं कर सकती, उसी उद्देश्य के साथ इस बार होली मनेगी।

## दिल्ली से लखनऊ जा रही शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन के पार्सल कोच में लगी आग

नई दिल्ली-ब्यूरो  
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस की जेनरेटर मीलने ही रेल अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों ने तत्काल

रेलगाड़ी सुबह करीब 6:41 बजे गाजियाबाद स्टेशन पहुंची और आग बुझाने वाले यंत्रों से धुएं को काबू करने में सफलता नहीं मिलने पर दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। प्रभावित कोच को रेलगाड़ी से अलग किया गया और इसके बाद रेलगाड़ी को सुबह 8:20 बजे गंतव्य के लिए रवाना किया गया। हालांकि, आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की लगेज बोगी में आग क्यों लगी। इस घटना को लेकर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।

कार में आग लग गई। स्टेशन पर ट्रेन की लगेज बोगी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की सूचना

लखनऊ शताब्दी ट्रेन की जेनरेटर कार को ट्रेन से अलग किया है। अधिकारियों ने बताया कि रेलगाड़ी में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं।

## माजपा दुनिया में सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी : ममता

कोलकाता-ब्यूरो  
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को भाजपा की आलोचना करते हुए उसे दुनिया में 'सबसे बड़ी लुटेरी' पार्टी बताया और कहा कि उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। पूर्वी मिदनापुर जिले के हल्दिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भगवा पार्टी पर दंगों की साजिश रचने, लोगों की हत्या करने तथा दलित लड़कियों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया।

## भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त उपग्रह मिशन पर कर रहे है काम : इसरो

रिफ्लैक्शन ब्यूरो  
भारत और फ्रांस तीसरे संयुक्त उपग्रह मिशन पर काम कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच

फ्रांसीसी कंपनियां उन अवसरों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार हेतु राष्ट्रीय परिषद (एनसीएसटीसी) और 'विज्ञान प्रसार' द्वारा आयोजित डिजिटल कार्यक्रम में कहा, 'फ्रांस अंतरिक्ष में भारत का सबसे बड़ा साझेदार है।' 'भू-स्थानिक डेटा और मानचित्रण में भारत की अंतरिक्ष संबंधी क्षमताओं को बढ़ाने' के विषय पर डीएसटी (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) स्वर्ण जयंती संवाद के दौरान सिवन ने यह बात कही। इसरो अधिकारियों के अनुसार, इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस ने दो संयुक्त मिशन अवसर पैदा किए हैं, कई

## इस सरकार ने बढ़ाई बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी : राहुल

रिफ्लैक्शन ब्यूरो  
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर हैं। इस बीच कांग्रेस नेता ने शनिवार को केंद्र सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि इस सरकार ने क्या बढ़ाया? बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और सिर्फ मित्रों की कमाई। उन्होंने ट्वीट के साथ एक खबर को भी शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना से पहले 9.9 करोड़ लोग मध्यम आय वर्ग का हिस्सा थे जिनकी संख्या घटकर 6.6 करोड़ रह गई है। इस खबर के मुताबिक 2011 से 2019 के बीच 5.7 करोड़ लोग निम्न आय वर्ग से निकलकर मध्यम आय वर्ग का हिस्सा बने थे। रोजाना डेढ़ सौ रुपये या उससे कम कमाने वालों की संख्या 7.5 करोड़ जा पहुंची है। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने शुरुवार को आरोप लगाया कि देश अब भी अनियोजित लॉकडाउन का दंश झेल रहा है।

## 111 दिनों के बाद कोरोना ने तोड़ा एक बार फिर रिकॉर्ड

रिफ्लैक्शन ब्यूरो  
भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 40,953 नए मामलों दर्ज किए गए जो 111 दिनों में एक ही दिन में आए सर्वाधिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,15,55,284 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के मामलों में लगातार 10वें दिन वृद्धि दर्ज की गई है। देश में अब भी 2,88,394 लोग संक्रमित हैं जो संक्रमण के कुल मामलों का 2.49 प्रतिशत है, जबकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर गिरकर 96.12 प्रतिशत रह गई है। सुबह आठ बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार



एक दिन में आए 40,953 नए मामले पिछले 111 दिनों में सर्वाधिक हैं, जबकि 188 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 1,59,558 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 1,11,07,332 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं जबकि मृतक दर 1.38 प्रतिशत है। भारत में कोविड-19 के मामले सात अगस्त को 20 लाख का आंकड़ा पार कर गए थे। इसके बाद संक्रमण के मामले 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40

## आरएसएस में 12 साल बाद बड़ा परिवर्तन : होसबोले

रिफ्लैक्शन ब्यूरो  
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) में 12 साल बाद बड़ा परिवर्तन हुआ है। आरएसएस के नए सरकारीवाह (महासचिव) पद पर दत्तात्रेय होसबोले का सर्वसम्मति से चयन हुआ है। वह पिछले 12 वर्ष से लगातार इस पद पर काम कर रहे सुरेश भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बेंगलुरु के जनसेवा विद्या केंद्र में चल रही अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में शनिवार को यह निर्णय लिया गया। बेंगलुरु में 19 मार्च से अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू हुई थी, दूसरे दिन शनिवार को सरकारीवाह पद पर चयन हुआ। दरअसल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ही

संघ निर्णय लेने वाली सर्वोच्च ईकाई है। हर वर्ष अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग होती है। संघ में हर तीन वर्ष पर सरकारीवाह यानी महासचिव पद पर चयन होता है। वर्ष 2009 से लगातार सुरेश भैयाजी जोशी सरकारीवाह की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उन्हें 2018 की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की मीटिंग में एक और कार्यकाल मिला था।



## राजनाथ ने की अमेरिकी समकक्ष ऑस्टिन से वार्ता

रिफ्लैक्शन ब्यूरो  
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को विस्तृत वार्ता की, जिसमें द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देने, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बदलती स्थिति और आतंकवाद की चुनौती जैसे विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा

दर्शनी की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। ऑस्टिन शनिवार सुबह राष्ट्रीय स्मारक गए और भारत के 'मल्टी-मिशन' सशस्त्र प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की योजना पर भी ऑस्टिन और सिंह के बीच चर्चा होने की



की गई। ऑस्टिन 3 देशों की यात्रा के कार्यक्रम के तहत जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के बाद भारत आए हैं। इस यात्रा को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन की क्षेत्र में अपने निकट सहयोगियों एवं साझेदारों के साथ संबंधों को लेकर मजबूत प्रतिबद्धता

शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वार्ता से पहले उन्हें विज्ञान भवन परिसर में सलामी गारद दिया गया। ऑस्टिन की यात्रा संबंधी जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि 3 अरब डॉलर से अधिक (अनुमानित) की लागत से अमेरिका से करीब 30 उम्मीद है। क्राइ समूह की बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का संकल्प लेने के कुछ दिनों बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री की भारत की यात्रा हो रही है। 4 देशों के इस समूह में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।



## विश्व भर में बसे भारतवंशियों का तीर्थ भारत



पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या में कुछ समय पहले अवतार सिंह सेहमी नाम के एक भारतवंशी सज्जन का निधन हो गया। वे करीब 90 साल के थे। उनकी एक हसरत पूरी नहीं हुई, इस कारण केन्या में बसे भारतीय मूल के काफी लोग उदास हैं। सेहमी चाहकर भी कभी अपने पुरखों के वतन भारत नहीं जा सके। उनके माता-पिता 1890 के आसपास पंजाब से मुंबई होते हुए केन्या गए थे। ब्रिटिश सरकार पंजाब से



संपादक-  
नीतू कपूर

जबरन हजारों लोगों को केन्या में रेल नेटवर्क बिछाने के लिए लेकर गई थी। उनमें सेहमी के माता-पिता भी थे। दरअसल इस त्रासदी से लाखों भारतवंशी हर साल गुजरते रहते हैं। वे कभी अपने पुरखों के देश या अपने पुरखों की जन्मभूमि के दर्शन कर नहीं पाते हैं। सेहमी समाजसेवी और भारतीय मूल के लोगों के बीच में काफी सक्रिय और लोकप्रिय थे। पर वे अधूरी हसरत को लेकर संसार से विदा हो गए। जो आर्थिक रूप से सम्पन्न भारतवंशी होते हैं वे तो कभी न कभी भारत आ ही जाते हैं। यहां आकर वे कुछ बड़े महानगरों के अलावा अपने गांव, शहर, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बनारस, अमृतसर वगैरह जाना चाहते हैं और चले भी जाते हैं। इस तरह उनकी अपने भारत में जाने की इच्छा पूरी हो जाती है। दुर्भाग्यवश यह सुख सबको तो नसीब नहीं होता। देखिए कि भारतवंशी सात समंदर पार बसकर भी भारतीय ही कहलाते हैं। उनके साथ ही रहते हैं उनके भारतीय संस्कार, मूल्य, मर्यादाएं और नैतिकताएं। मोटे अनुमान के मुताबिक, इस समय सारी दुनिया में ढाई करोड़ से अधिक भारतवंशी दुनिया के चप्पे-चप्पे में हैं। यह एक बड़ी संख्या है जो पचासों छोटे देशों से अधिक है। दुबे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी बने हैं या अभी भी हैं। ये दर्जनों देशों की संसद में भी हैं। मतलब ये जिधर गए और बसे, वहां ये रचनात्मक रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। यह उन देशों के सबसे खासमखास पदों पर पहुंच गए। पर यह तस्वीर का एक पहलू ही है। ये सब जगह धनी नहीं हैं। हालांकि मीडिया तो सिर्फ सफल कहानियों को ही पेश करता है। तो जो धनी नहीं हैं उनके लिए जीवन में कम से कम एकबार भारत जाना भी संभव नहीं हो पाता है। ये जीवनभर ईश्वर से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि इन्हें कम से एकबार भारत देखने का सुख मिल जाए। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक वी.एस.नायपाल 1960 के दशक में पहली बार भारत आए थे। वे लंदन से मुंबई पहुंचे। संयोग से वह दिवाली की रात थी। वे सारे वातावरण को देखकर इतने अभिभूत हुए कि वे उस रात का बार-बार उल्लेख किया करते थे। उसके बाद तो वे बार-बार भारत आते रहे। उन्होंने भारत की कई स्तरों पर निंदा भी की, पर वे भारत के प्रति अगाध प्रेम का भाव भी रखते थे। अगर आप खेलप्रेमी हैं तो आपने देखा होगा कि लंदन से लेकर डरबन और मेलबर्न से लेकर कुआलालम्पुर के मर्डेका स्टेडियम तक भारतवंशी भारतीय टीमों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वे उस देश की टीम को सामान्यतः सपोर्ट नहीं करते जिधर वे या उनके परिवार लंबे समय से बसे हुए हैं। हां, जब उस देश का मैच भारत से हटकर किसी अन्य से होता है तो वे अपने निश्चय ही अपने वर्तमान देश के साथ होते हैं।

# पंजाब रिफ्लैक्शन

## चुनावी घोषणा पत्रों का पिलारा

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों ने चुनावी घोषणा पत्र जारी करने शुरू कर दिए हैं। घोषणा पत्र हर राजनीतिक दल सत्ता में आने पर अपने कार्यक्रमों और नीतियों का प्रारूप पेश करता है। लोक लुभावन वादे किए जाते हैं ताकि मतदाता आकर्षित होकर उन्हें वोट डाल सकें। दक्षिण भारत की राजनीति में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त रेडियो बांटने का सिलसिला काफी पुराना है। तमिलनाडु की सियासत में दिवंगत द्रमुक प्रमुख एम. करुणानिधि के 2006 के घोषणा पत्र में मुफ्त रंगीन टीवी और अन्य चीजों का वादा किया था, उसके बाद तो राजनीतिक दलों के बीच ऐसे वादों जैसे मुफ्त लैपटॉप, दुधारू गाय, मिक्सर ग्राइंडर और सोने के मंगलसूत्र की होड़ लग गई। अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेत्री अम्मा जयललिता भी जनता के वोट बटोरने के लिए ऐसे ही उपहारों की घोषणा हर चुनाव में करती थीं। तमिलनाडु में 1937 से लेकर 1971 तक पूर्ण शराबबंदी लागू थी जब एम. करुणानिधि के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो द्रमुक सरकार ने शराबबंदी को हटा दिया था। इस बार के चुनाव में अन्नाद्रमुक और द्रमुक ने शराब मुक्त तमिलनाडु का वादा किया है। दोनों ही दलों के चुनावी घोषणा पत्र में शराबबंदी का उल्लेख एक संदर्भ है जिससे संकेत मिलता है कि इसे लागू करने की कोई-प्रतिबद्धता नहीं है। दोनों ही दल ऐसी रेडियो

बांटने के वादे पर एक सा जान पड़ रही हैं। इतना ही नहीं उन्होंने नागरिकता कानून के निरस्त करने और राजीव गांधी हत्याकांड के 7 अभियुक्तों को रिहा करने जैसे विवादास्पद वादे भी कर डाले। तमिलनाडु पहले ही भारी कर्ज में डूबा

की भी घोषणा की है। यद्यपि ममता बनर्जी ने अपने किए गए कामों पर अपनी पीठ थपथपाई है लेकिन पांचों राज्यों के मतदाता किसके वादे पर कितना भरोसा करते हैं यह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लगभग सभी दलों ने अपनी-अपनी ढपली पर



हुआ है, ऐसे में इन वादों पर एक बहस छिड़ गई है। चुनावी वादे करने में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल अध्यक्ष ममता बनर्जी भी पीछे नहीं हटीं। उन्होंने घर-घर राशन पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को एक हजार रुपए, ओबीसी और एससी, एसटी के लिए प्रति वर्ष 12 हजार रुपए दिए जाएंगे। सामान्य परिवार के लोगों को प्रति माह 500 रुपए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को एक हजार रुपए दिए जाएंगे। किसानों को हर वर्ष 6 हजार मिलता लेकिन अब किसानों को दस हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने छात्रों को टैक्स लेने के लिए दस हजार का क्रेडिट कार्ड देने

अपना-अपना राग अलापना शुरू कर दिया है लेकिन इन वादों के जमीन पर लागू होने के संबंध में हर बार की तरह संदेह का वातावरण बना हुआ है। अधिकांश मतदाता यह मानते हैं कि ये घोषणा पत्र चुनावों के बाद रद्दी की टोकरी की शोभा बढ़ाएंगे और लोग बस यही कहेंगे-झूठ है तेरा वादा-वादा तेरा वादा। कोरोना महामारी के चलते अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है। केन्द्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी राजस्व की कमी का सामना कर रही हैं ऐसी स्थिति में उम्मीदें कम हैं कि यह घोषणाएं जमीनी स्तर पर लागू होंगी। लोकतंत्र में इस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण घोषणाएं और आश्वासन राजनीति को

दूषित कर रहे हैं जो न केवल लोकतंत्र का उपहास है बल्कि एक बड़ी विसंगति का द्योतक है। राजनीतिक दलों में पनप रही ये मुफ्त बांटने की संस्कृति को क्या लोभ की राजनीति नहीं माना जाना चाहिए? यह कैसा लोकतांत्रिक ढांचा बन रहा है, जिसमें पार्टियां अपनी सीमा से कहीं अधिक बढ़कर घोषणाएं कर रही हैं। इन्हें किसी भी तरह से जनहित नहीं कहा जा सकता। अब सवाल यह है कि क्या सार्वजनिक संसाधन किसी को बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए? इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति पनप रही है। जनता का कोई भी सुविधा मुफ्त मुहैया कराने पर सरकार के कोष पर जो बोझ पड़ता है क्या उसकी भरपाई जनता से ही नहीं की जाती? अब जबकि सरकारें आर्थिक रूप से आरामदेह स्थिति में नहीं हैं तो फिर ऐसी घोषणाएं लागू करने के लिए धन कहां से आएगा। सवाल यह भी है कि देश का टैक्सदाता मुफ्तखोर समाज को कब तक पालेगा? क्या वादाखिलाफी करने वाले दलों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? कोई ऐसा कानून जरूर बनाया जाना चाहिए जिसकी वादाखिलाफी करने वाले दलों के विरुद्ध चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सके परन्तु ऐसा कानून कौन बनाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि राजनीतिक दल विवेक से काम लें और वही घोषणाएं करें जो जमीनी स्तर पर लागू हो पाए। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो लोकतंत्र को काफी नुकसान हो सकता है। इस मुद्दे पर मंथन होना ही चाहिए।

## गडकरी की नई 'स्क्रैप नीति'

इस वास्तविकता से बहुत कम लोग ही असहमत हो सकते हैं कि केन्द्रीय सड़क व परिवहन मन्त्री श्री नितिन गडकरी मोदी मन्त्रिमंडल के नवरत्नों में से सबसे ज्यादा जगमगाते रत्न हैं। वह अपनी नीतिगत दूरदर्शिता के लिए राजनीति में पक्की पहचान बना चुके हैं। राजनीतिज्ञ का काम राजनीति को जमीन पर कलात्मक रूप में उतारने का होता है। इस कार्य में भविष्य की चुनौतियों का निपटारा करना उसके लक्ष्य पर इस प्रकार रहता है कि भावी पीढ़ियों का जीवन सुगम बने। श्री गडकरी ने लोकसभा में जिस 'मोटर वाहन स्क्रैप नीति' की घोषणा की है वह इसी तथ्य का ही प्रतीक है। इसमें आने वाली पीढ़ियों के साथ ही वर्तमान पीढ़ी को भी सुरक्षा का वातावरण देने व पर्यावरण को आधिकारिक प्रदूषण मुक्त रखने की नीयत समाहित है। श्री गडकरी ऐसे सड़क परिवहन मन्त्री कहलायेंगे जिनके नेतृत्व में देश में सर्वाधिक राजमार्गों का निर्माण हो रहा है और अधिक से अधिक शहरों को आपस में त्वरित मार्गों से जोड़ा जा रहा है। वह दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल दो घंटों में तय करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं मुंबई से पुणे तक की दूरी उन्होंने आधे समय में ही पूरी करने की योजना को लागू कर डाला है। मगर यह भी देखना है कि जल मार्गों के निर्माण के वादे और उनकी घोषणाओं का हश्च क्या होता है? जहां तक पुराने मोटर वाहनों को सड़कों से दूर रखने का सवाल है तो

उन्होंने इस बारे में विस्तृत खाका खींचते हुए आम जनता को इस प्रकार राहत देने का वादा किया है कि लोग अपने 20 साल पुराने वाहन बेच कर नये वाहन खरीदने के लिए प्रेरित हो सकें। श्री गडकरी प्रयोगवादी मन्त्री



भी हैं जो लगातार बेहतर के लिए प्रयोग करना जरूरी समझते हैं। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र नागपुर में बिजली से चलने वाली बस चला कर पूरे देश में इसका प्रचलन बढ़ाया और आज हालात यह हैं कि प. बंगाल का कोलकाता शहर इस क्षेत्र में दुनिया के छह बड़े शहरों में से एक है। वह जब नया मोटर वाहन कानून लाये तो कई राज्यों ने इसका विरोध भी किया परन्तु उनकी मंशा साफ थी कि भारत में सड़कों पर यातायात सुरक्षित व नियन्त्रित तरीके से हो और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कम से कम हो। वाहन चालकों में आदमी की जान की कीमत का महत्व

इस तरह बने कि वह 'स्व नियन्त्रण' को सुरक्षाचक्र की भांति ले। जहां तक पुराने मोटर वाहनों को सड़कों से दूर करने और इन्हें कबाड़ या स्क्रैप में तब्दील करने की नीति का सवाल है तो श्री गडकरी ने साफ कर दिया है कि

15 साल पुराने वाणिज्यिक व 20 साल पुराने निजी वाहनों को अब सड़क पर तभी चलाया जा सकेगा जब वे 'फिटनेस सर्टिफिकेट' (चालन दक्षता प्रमाणपत्र) ले लेंगे। नये नियमों के तहत इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने की फीस बीस गुना अधिक तक हो सकती है। इसका मतलब यही निकलता है कि श्री गडकरी पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रेरित करने के बजाय उन्हें स्क्रैप में तब्दील करने को प्रेरित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ऐसा नीति घोषित की है जिससे पुराने वाहनों के मालिक नये वाहन खरीदने को स्वतः प्रेरित होंगे। मसलन अपने पुराने वाहन को स्क्रैप में तब्दील

कारने का सबूत हासिल करने वाले व्यक्ति को नया वाहन पांच प्रतिशत कम दाम पर कम्पनी से ही मिलेगा। (इसके लिए गडकरी मोटर कम्पनियों से बात कर रहे हैं) और बैंकों से वित्तीय मदद के रास्ते खुले रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप में तब्दील करने वाले वाहन मालिकों को बैंक और अधिक सुगमता से कर्ज देंगे। इसके साथ ही राज्य सरकारों से परिवहन मन्त्री बात कर रहे हैं कि वे स्क्रैप सबूत रखने वाले वाहन मालिकों को सड़क कर (रोड टैक्स) में 25 प्रतिशत की छूट दें और पंजीकरण फीस भी माफ कर दें। श्री गडकरी ने नये वाहनों की खरीद पर जीएसटी की दरें भी कम करने की अपील की है। ये सब फैसले श्री गडकरी इसीलिए ले रहे हैं जिससे भविष्य में वायु प्रदूषण कम से कम हो सके और पेट्रोल ईंधन खर्च भी किफायती हो सके। इसके लिए पूरे देश में वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने वाले समन्वित केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। ऐसा पहला केन्द्र गुजरात के 'अलंग' में बनेगा जो पहले से ही पुराने पानी के जहाजों को कबाड़ में तब्दील करने का एक केन्द्र है। इस नीति की शुरुआत श्री गडकरी सबसे पहले सरकार द्वारा प्रयोग किये जा रहे वाहनों से ही करेंगे जिससे निजी क्षेत्र के लोग प्रेरणा ले सकें। फिलहाल विभिन्न सरकारी विभागों के पास दो लाख 37 हजार ऐसा वाहन हैं जो 15 साल पुराने हैं।

# ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ-ਸੋਨੀ

# ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ

**ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਬਿਊਰੋ**  
ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੀ.ਬੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੇਂ ਜਨਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟਿਕ ਆਹਾਰ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ



ਹੋਣਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ: ਨਰੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀ.ਬੀ. ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ. ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ: ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਬੀ. ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800116666 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਸਲਰ ਵਿਕਾਸ ਸੋਨੀ, ਐਨ ਐਸ ਯੂ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

**ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ-ਸਹਿਤ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ**



ਅਦਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦੀ, ਸਮਝੌਤਾ-ਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਚੈਕ ਬਕਾਇਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ,

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ/ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ

ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਟੌਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

# ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 15372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

# ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ

**ਤਰਨ ਤਾਰਨ-ਬਿਊਰੋ**  
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 15372 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ 898 ਸੈਂਪਲ ਹੋਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ. ਟੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਆਰ., ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਤੇ ਟਰੂਨੈੱਟ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 183776 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 180010 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 838 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2636 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ



ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 2222 ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ 60 ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 02 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 58 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 289 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 183 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 04 ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 03 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰਹਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ।

ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ 820 ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ 777 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ

**ਮਾਨਸਾ-ਬਿਊਰੋ**  
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 135 ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ



ਗਏ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਮਾਸਕ ਮੁਫਤ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਸਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਟੀ 1 ਅਤੇ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਟੀ 2 ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ

# ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ



**ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਬਿਊਰੋ**  
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਲਾਕ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਦੀਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਬੰਨਾਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟ ਹਨ, ਉਹ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਦੀਨਾਂ ਉਪਰ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੇ ਨਰਮੇ/ਕੁਪਾਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਮਿੱਲੀ ਬੱਗ ਆਦਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਬੂਟੀ, ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ, ਧੜੂਰਾ, ਕੰਗੀ ਬੂਟੀ, ਭੰਗ, ਪੁੱਛ-ਕੰਡਾ, ਦੋਧਕ, ਚੁਲਾਈ, ਤਾਦਲਾ ਭੰਗੋਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਪੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੋਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਟਰਵਰਕਸ, ਸਕੂਲ ਸਮਸਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੋਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨਦੀਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।



ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਮਿੱਲੀ ਬੱਗ ਆਦਿ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਲੀ ਬੂਟੀ, ਗਾਜਰ ਬੂਟੀ, ਧੜੂਰਾ, ਕੰਗੀ ਬੂਟੀ, ਭੰਗ, ਪੁੱਛ-ਕੰਡਾ, ਦੋਧਕ, ਚੁਲਾਈ, ਤਾਦਲਾ ਭੰਗੋਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਪੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਰੋਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਨਹਿਰਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਟਰਵਰਕਸ, ਸਕੂਲ ਸਮਸਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੋਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਨਦੀਨ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

# ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾओं के लिए खेल प्रतियोगिता



ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬ੍ਰੂਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵितरित की जा रही स्पोर्ट्स किट से मुख्य रूप से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को बड़ी संख्या में लाभ होगा। उन्होंने आज यहां निकटवर्ती गांव पामल में एक फुटबॉल टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए, अध्यक्ष बਿੰਦਰਾ ਨੇ कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली



ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੁਵਾओं में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इस अवसर पर इस टूर्नामेंट के विजेताओं को खेल किट भी वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि इस तरह के टूर्नामेंट राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित किए जा रहे हैं और इस विशेष टूर्नामेंट में 32 गांवों की टीमों ने भाग लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए यूथ सर्विसेज क्लब, ग्राम पमाल के प्रयासों की भी सराहना की।

## पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की सूची जारी

हमीरपुर-ब੍ਰੂਰੋ

जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों के खाली पदों पर होने वाले चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) देवाश्वेता बनिक् ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार कुल 14 मतदान केंद्रों में से एक मतदान केंद्र संवेदनशील और एक मतदान केंद्र को अति संवेदनशील घोषित किया गया है।

## 6 लोग निकले कोरोना पॉजीटिव

हमीरपुर-ब੍ਰੂਰੋ

जिला में शनिवार रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट में 3-3 लोग कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अर्चना सोनी ने बताया कि जिला में शनिवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए कुल 399 सैंपल लिए गए, जिनमें से 3 पॉजीटिव निकले। पॉजीटिव पाए गए लोगों में मटाहणी का 35 वर्षीय



व्यक्ति, डुगली क्षेत्र के गांव भरनोट का 56 वर्षीय व्यक्ति और नादोन के वार्ड नंबर 5 का 22 वर्षीय युवक शामिल है। डॉ. अर्चना सोनी ने बताया कि आरटी-पीसीआर टेस्ट में सलासी के 53 वर्षीय व्यक्ति, नादोन के गांव नरारडा की 45 वर्षीय महिला और कनोह की 40 वर्षीय महिला की रिपोर्ट पॉजीटिव आई है।



जिला प्रशासन और लुधियाना पुलिस द्वारा गठित मोबाइल टीमों ने बिना मास्क पहने लोगों के रैपिड कोरोना टेस्ट किये ऐसे घोर लापरवाही के कारण कोविड फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लुधियाना में स्वास्थ्य विभाग की मदद से संयुक्त टीमों का गठन किया गया है।

## लाल कुर्ती बाजार का अरमान हत्याकांड : परिवार ने CBI जांच के लिए हाईकोर्ट में की याचिका दायर : सुनीता (अरमान की मां)



पंजाब रिफ्लेक्शन न्यूज़-राकेश कुमार जालंधर कैंट स्थित लाल कुर्ती बाजार में प्रेक के बहाने दोस्त द्वारा कत्ल किए गए NRI के बेटे व केंद्रीय विद्यालय 4 के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले अरमान का बहुचर्चित मामला फिर चर्चा में आ गया है। बच्चे की मां ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने इस मामले में सही सुनवाई नहीं की। अब उन्होंने छद्म जांच के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। पंजाब प्रेस क्लब में अरमान की मां सुनीता ने कहा कि पुलिस न तो इस मामले के असल कारण तक पहुंच सकी है और न ही कत्ल में शामिल बाकी लोगों को तलाश पाई है। यही नहीं, आरोपी अब जेल में सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए आरामदायक ज़िंदगी बिता रहा है। सुनीता ने कहा कि पुलिस ने दावा किया था कि स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की अरमान को चाहती थी, इससे खफा होकर दूसरे छात्र ने अरमान को मारा। अगर ऐसा था तो पुलिस ने उस लड़की को केस में शामिल क्यों नहीं किया, जबकि लड़की इससे मुकर चुकी है कि उसका इन दोनों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उन्होंने कहा कि यह प्री-प्लान्ड मर्डर था क्योंकि कातिल सब सामान लेकर आया था तो उसके साथ बाकी लोग भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने किसी दूसरे को नहीं पकड़ा।





